

राजस्थान सरकार
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राजस्थान)

विविध :: 66/2019

प्रार्थी
“एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक
लिमिटेड” (जो पूर्व में “ए.यू.
फाइनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड)
19-ए, घुलेश्वर गार्डन, अजमेर
रोड, जयपुर 302001 जरिये
प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री जयपाल सिंह रावत पुत्र रतनसिंह रावत
पता-160, राईका का वास, ग्राम नहारपुरा
तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान
306001 द्वितीय पता- प्लॉट अवस्थित खसरा
नम्बर 2906, पट्टा नम्बर 26, मिसल नम्बर
1/2013 एवं 2014, ग्राम नहारपुरा, ग्राम
पंचायत प्रतापगढ़, तहसील रायपुर जिला
पाली राजस्थान
2. श्रीमती गौरी देवी पत्नी जयपालसिंह रावत
पता-160, राईका का वास, ग्राम नहारपुरा,
तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान
306001
3. श्री धरम सिंह पुत्र मांगुसिंह पता-62, मुख्य
ग्राम शोदपुरा, तहसील रायपुर जिला पाली
राजस्थान 305901



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स
एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (The Securitisation and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

आदेश

दिनांक : 1.11.2019

प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के
तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया गया ।

प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 बैंक का ऋणी है।
अप्रार्थी संख्या 2 बैंक के सहऋणी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 बैंक के जमानती है। अप्रार्थी
संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 31.03.2014 को 9,00,000/- (अक्षरे नौ लाख रुपये)
अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदन कर मोरगेज ऋण प्राप्त किया तथा
ऋणी/जमानती ने उपरोक्त ऋण व उस पर देय ब्याज व खर्चों के लिए अपनी
प्रतिभूतिस्वरूप अचल सम्पति जो अप्रार्थी संख्या 01 जयपालसिंह रावत के नाम भारमुक्त
आवासीय सम्पति जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सम्पति प्लॉट अवस्थित खसरा नम्बर
2906, पट्टा नम्बरा 26, मिसल नम्बर 1/2013 एवं 2014, ग्राम नहारपुरा, ग्राम पंचायत
प्रतापगढ़, तहसील रायपुर जिला पाली जिला पाली, राजस्थान स्थित है जिसका क्षेत्रफल
108.6 वर्गगज है। जिसके उत्तर में देवीसिंह का मकान, दक्षिण में लक्ष्मणसिंह का मकान, पूर्व
में कॉमन चौक एवं निकासी एवं पश्चिम में स्वयं की भूमि है। अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण
इकरारनामा व साम्य मूलक बंधक सृजन करने का पत्र आदि दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर
कर निष्पादित किया। अप्रार्थीगण ने ऋण प्राप्त करने के पश्चात ऋणी/जमानती ने ऋण
इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप ऋण खाते का संचालन नहीं किया, जबकि अप्रार्थीगण को
अपने उपरोक्त ऋण खाते का संचालन निष्पादित इकरारनामा के शर्तों के अनुरूप करना
था। अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की सम्पति को प्रार्थी बैंक के पास जरिये Mortgage by
deposit of title deeds के बंधक रखा। अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबन्ध शर्तों के अनुरूप उक्त
खाते में लेनदेन नहीं किया एवं इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप देय राशि व ब्याज का
भुगतान नहीं किया, जो ऋण अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थीगण को उक्त अधिनियम

क्रमश पृष्ठ :: 2

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 24.06.2019 को देकर बकाया राशि मय ब्याज के 5,96,958/- अक्षरे पांच लाख छिन्नवें हजार नौ सौ अठावन्न रूपये के मांग हेतु नोटिस दिया गया। देय नोशनल ब्याज व खर्चों की मांग की गई लेकिन ऋणी ने प्रार्थी बैंक को देय समस्त राशि का भुगतान नोटिस देने के उपरान्त भी नियत अवधि में नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखे गये स्वामित्व की सम्पत्ति का कब्जा एवं इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपये 9,00,000/- अक्षरे नौ लाख रूपये का ऋण दिया उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये। प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण ने बैंक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है :

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset - (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him --

- (a) Take possession of such asset and documents relating thereto; and
- (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पाली को भेजकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति स्वरूप अपने स्वामित्व की सम्पत्ति जो ऊपर वर्णित किया है, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली को निर्देशित करें कि वे उक्त भूमि का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी बैंक को संभलाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की एक प्रति थानाधिकारी, रायपुर, जिला पाली एवं प्रार्थी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश सुनाया गया।



(दिनेश चन्द जैन)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली